Chapter 7

bihar board 8th history notes ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा

ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा

पाठ का सारांश-अंग्रेजों ने भारत में पूर्व की प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में अपने स्वार्थ के मद्देनजर बदलाव कर दिया था।
अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे :- अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया। दरअसल शुरू में अंग्रेज भारत के प्रचलित कानूनों और परम्पराओं को जानना चाहते थे। इसलिए 1781 में कलकत्ता में स्थापित 'मदरसा' और बनारस में स्थापित 'संस्कृत कॉलेज' को प्रश्रय दिया गया। विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी अपनी रुचि के लिए भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को पूरी तरह जानना चाहते थे। किन्तु बाद में कुछ भारतीयों को शासन के काम के लायक अंग्रेजी में शिक्षित करना जरूरी समझा गया।

शिक्षा नीति संबंधी विवाद:- 1813 ई. में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रति वर्ष एक लाख रुपया खर्च करना निश्चित किया था। विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज चाहते थे कि यह पैसा भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। राजा राममोहन राय ने भी इंगलैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की।

जबकि जेम्स मिल और मैकाले जैसे अंग्रेज अधिकारी मानते थे कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं। वे भारतीयों को अंग्रेजी में, व्यावहारिक शिक्षा देना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारतीय जानें कि इंगलैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर सके । मैकाले ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी।

अंग्रेज सरकार ने मैकाले के पक्ष को मानते हुए 1835 में एक अधिनियम पारित कर भारत में ऊँची शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी निश्चित कर दिया । तय हुआ कि भारतीय भाषाओं वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और स्कूल स्तर की शिक्षा को छेड़ा नहीं जाएगा।

व्यवसाय के लिए शिक्षा:-1854 में अंग्रेजों ने शिक्षा संबंधी एक और नीति बनाई । इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को अंग्रेजी में आधुनिक शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उनका मानस भारतीय से बदलकर यूरोपीय हो जाए और भारतीय अंग्रेजी प्रशासन के काम में आने लायक बन सकें।
1854 की नीति का महत्व:- प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। 1857 में, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय बनाये गये । हम जिस प्रकार का पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई का तौर-तरीका देख रहे हैं, वह 1854 के बाद से ही अस्तित्व में आया है।
स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ—तब स्थानीय पाठशालाएँ आपकी तरह नियमित तौर पर चलने वाले स्कूलों में

https://www.evidyarthi.in/

नहीं होती थी। गुरुजन अपने घरों के एक हिस्से में, पेड़ के नीचे, मंदिर पर आदि स्थानों पर बच्चे पढ़ते थे। शिक्षा मौखिक दी जाती थी। अमीर बच्चों से ज्यादा फीस ली जाती थी जबकि गरीब बच्चों से कम । फसलों की कटाई के समय कक्षाएँ बंद हो जाती थीं।
गाँव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करते थे।
नई दिनचर्या, नए नियम:-1854 के बाद कंपनी ने उच्च शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा में सुधार का फैसला किया। पाठशाला बनवाए गए। पंडितों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया । अव अध्ययन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होने लगा। विद्यार्थियों से नियमित शुल्क लिया गया, नियमित रूप से कक्षाएँ चलने लगीं। जो पाठशाला अंग्रेजी नियमों को नहीं मानती थी उन्हें अनुदान से वंचित कर दिया गया ।
राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची:-कुछ भारतीयों का भी मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। जबकि महात्मा गाँधी का मानना था कि-"अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है।" गाँधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। उनकी मान्यता थी कि भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए । गाँधीजी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर देती है लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है।
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में अपना स्कूल 'शांति निकेतन' शुरू किया था। उनके अनुसार स्कूल मुक्त और रचनाशील होने चाहिए, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें।
वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे । शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक, वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं।
कुछ भारतीय विचारक शिक्षा की एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके।
आधुनिक शिक्षा और बिहार:-शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए। 1911 ई. तक बिहार, बंगाल का ही हिस्सा था इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे बिहार अलग नहीं रहा। 1835 ई० में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का ढाँचा विकसित होने लगा । कई स्कूल और कॉलेज खोले गये । अंग्रेजों द्वारा भी और जमींदारों व अन्य बड़े परिवारों द्वारा भी। ईसाई धर्मप्रचारकों ने भारत के साथ-साथ बिहार के कई हिस्सों में स्कूलों को स्थापित कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ईसाईयों ने सबसे पहले बेतिया फिर पटना और दानापुर में शिक्षा का कार्य आरंभ किया। उनके द्वारा स्थापित पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेन्ट स्कूल (1853) एवं संत माइकल स्कूल (1854) आज भी बिहार के गिने-चुने अच्छे स्कूलों में आते हैं। इन स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफी बड़ा योगदान है। वर्तमान भारत के शैक्षणिक ढांचे की पृष्ठभूमि अंग्रेजों द्वारा स्थापित अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा ही रही।

https://www.evidyarthi.in/